

ध्यान रखें

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो संभव है कि आपको कंपनी की तरफ से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मिली हो और आपने खुद भी एक व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी ले रखी हो। ऐसे में, अगर किसी बीमारी या सर्जरी में अस्पताल का खर्च ज्यादा हो जाए, तो आप दोनों पॉलिसी का इस्तेमाल करके आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पेशा है अपराजिता शर्मा की रिपोर्ट....

अस्पताल के खर्च में राहत देती हैं दो बीमा पॉलिसियां



- एक से अधिक पॉलिसी के तहत बीमा दावा करने का तरीका**
- अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर पहली बीमा कंपनी को सूचित कर दें।
 - नकदरहित दावा करने के लिए स्वीकृति ले-जैसे ही बिल पहली पॉलिसी की बीमित राशि से ऊपर जाता है, दूसरी बीमा कंपनी को सूचित करें।
 - डिस्कॉप के समय बाकी की राशि अपनी जेब से चुकाएं
 - सभी मेडिकल बिल, डिस्काउंट विवरण और अन्य दस्तावेज एकत्र करें-पहली बीमा कंपनी से दावा निपटान पत्र प्राप्त करें।
 - दूसरी बीमा कंपनी को दावा फॉर्म, निपटान पत्र, मेडिकल बिल और केवाईसी दस्तावेज भेजें।
 - दूसरी कंपनी अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है।
 - आप पहली कंपनी से कह सकते हैं कि वे सत्यापित दस्तावेज दूसरी कंपनी को सीधे भेज दें।
 - जांच के बाद, दूसरी कंपनी रकम लौटाने की प्रक्रिया पूरी करेगी।
 - अगर भर्ती निर्धारित है, तो 48 घंटे पहले जानकारी दें।
 - कुछ बीमा कंपनियां उसी दिन ही निपटान पत्र देती हैं, तो कुछ 30 दिन लेती हैं।

कौन सी पॉलिसी पहले चुनें

- कॉरपोरेट पॉलिसी को प्राथमिक रूप से चुनें
 - इसमें प्रतीक्षा अवधि कम होती है, साथ ही शर्तें भी कम होती हैं
 - इससे प्राइवेट पॉलिसी का नो-क्लेम बोनस बचता है
 - फैमिली प्लेटोर पॉलिसी में अन्य सदस्यों के लिए बीमा सुरक्षित रहता है
- कव चुनें निजी पॉलिसी**
- जब कॉरपोरेट पॉलिसी की बीमित राशि सीमा कम हो
 - यदि अस्पताल खर्च अधिक होने की आशंका हो

ध्यान देने योग्य बातें

- अगर दोनों बीमा कंपनियां कैशलेस क्लेम से इनकार करें, तो दो अलग बीमा राशि दावे दाखिल करें
- दोनों पॉलिसी एक ही कंपनी से हों, तो दोनों से नकद रहित दावे की संभावना होती है
- सब-लिमिट वाले उपचार में एक से ज्यादा पॉलिसी का उपयोग किया जा सकता है जैसे मेडरिन्टी बेनिफिट एक से अधिक पॉलिसी से लिया जा सकता है

लोगों ने साइका की कारो

सेटलमेंट लेटर आने में 30 दिन लगे और दूसरी कंपनी ने सभी बिल की सत्यापित कॉपी मांगी। -मयंक भूपेंद्र गोसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई

दो पॉलिसी होने से मेरे रिश्तेदार की चार महीने लंबी कीमोथैरेपी का खर्च पूरा हो पाया। -मयंक भूपेंद्र गोसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंबई

दिल्ली के बाद वॉलेटर पर जाना पड़ा। दूसरी पॉलिसी ने सिर्फ़ मेडरिन्टी सब-लिमिट तक ही कवर किया। -मंजू शर्मा, मैनेजर, फरीदाबाद

बाजार 30s

सेंसेक्स	निफ्टी
82330 -200.15	25019 -42.30
टॉप गेजर	टॉप गेजर
कंपनी बंद भाव बदलाव%	कंपनी बंद भाव बदलाव%
एनटीएल 245.75 1.38	बीएसएल 363.80 3.82
हिंद्यूनोर्लिबर 2381.00 1.10	टाटा कंज्यू 1170.00 1.99
टॉप लूजर	टॉप लूजर
एयरटेल 1814.35 -2.81	एयरटेल 1814.40 -2.83
एचसीएलटेक 1659.75 -2.14	एचसीएलटेक 1661.00 -2.06

कमोडिटी	भाव	बदलाव
सोना चांदी	96,450	+1400
	98,000	+1000

करेंसी	डॉलर/रुपया
	85.57 -0.03

एक्सप्रेसवे पर 240 किलोवाट क्षमता के बैटरी चार्जर स्थापित होंगे राजमार्गों पर 15 मिनट में वाहनों की बैटरी चार्ज करने की तैयारी

योजना

नई दिल्ली, एजेंसी। इलेक्ट्रिक वाहन से लंबे सफर पर निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि बैटरी खत्म होने पर उसे कैसे चार्ज करेंगे। चार्जिंग स्टेशन मिल भी गया तो बैटरी चार्ज करने के लिए घंटों इंतजार कौन करेगा। इन्होंने सब सवालों का हल निकालने की तैयारी सरकार ने कर ली है।



केंद्र सरकार राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और बस स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाले चार्जर लगाने का रणनीति है। एक्सप्रेसवे वे और हाइवे पर 240 किलोवाट क्षमता के चार्जर स्थापित होंगे। सभी जरूरी मंजूरी मिलने पर शेष स्टेशनों पर 360 किलोवाट के चार्जर लगेंगे जिससे वाहन कम समय में चार्ज हो सकेंगे।

इस समय शहरी इलाकों में 60 किलोवाट के चार्जर लगाए जा रहे हैं। आम तौर पर 60 किलोवाट का डीसी चार्जर एक इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने में एक घंटा लेता है। योजना के मुताबिक बढ़ी क्षमता वाले चार्जों से बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों

कर्नाटक में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन

देश में सबसे ज्यादा डीबी चार्जिंग स्टेशन 5879 कर्नाटक में हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 3842 स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश में 2113, दिल्ली में 1951 और तमिलनाडु में 1495 डीबी चार्जिंग स्टेशन हैं। केरल में 1288 तो वहीं राजस्थान में 1285 स्टेशन हैं। गुजरात में 1008 स्टेशन हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, सरकार, सरकार के विद्युत मंत्रालय ने देश में जनता के लिए स्थापित किए गए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का एक राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस विकसित करने के मकसद से 'ईवी यात्रा' पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए डीबी का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति निकटतम चार्जिंग स्टेशनों को ट्रैक कर सकता है। 'ईवी यात्रा पोर्टल' www.evyatra.beedindia.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोगकर्ताओं को राष्ट्रीय व प्रदेश राजमार्गों और शहरों में चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने के लिए नए वेब पोर्टल विकसित कर रहा है। इस पोर्टल से वास्तविक समय पर सूचना और भुगतान के माध्यमों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। नया ऐप कार्यरत रहे डीबी चार्जिंग स्टेशनों की वास्तविक समय की जानकारी, चार्जर क्षमता, स्थान की उपलब्धता, फीडबैक सुविधा और ऑनलाइन भुगतान के विकल्प के बारे में जानकारी देगा।

संयुक्त राष्ट्र ने भारत की वृद्धि का अनुमान घटाया निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर की मुनाफावसूली

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने एफआरआई जारी की। इसमें उसने कहा कि भारत, अनुमानित नरमी के बावजूद लचीले उपभोग तथा सरकारी व्यय के सहारे सभ्य तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भले ही भारत के 2025 में वृद्धि अनुमानों को घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है फिर भी वह मजबूत निजी खपत तथा

अर्थव्यवस्था 2025 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान

सार्वजनिक निवेश के बल पर सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 2024 के 7.1 प्रतिशत से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित मोड़ पर है, बढ़ते व्यापार तनाव एवं उच्च-नीति अनिश्चितता के कारण यह स्थिति बनी है।

मुंबई, एजेंसी। आईटी शेयरों और भारत एयरटेल में मुनाफावसूली होने से शुक्रवार को स्थानीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। मानक सूचकांक संसेक्स में 200 अंक और निफ्टी में 42 अंक की सुस्ती रही। विश्लेषकों ने कहा कि पिछले सत्र में बाजार के सात महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली को तरजीह दी। संसेक्स 200.15 अंक गिरकर 82,330.59 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 383.79 अंक गिरकर 82,146.95 अंक पर आ गया था। निफ्टी भी 42.30 अंक यानी 0.17 प्रतिशत गिरकर 25,019.80 अंक पर बंद हुआ। स्थानीय शेयर बाजारों में इस सप्ताह शानदार तेजी देखी गई। साप्ताहिक आधार पर संसेक्स ने 2,876.12 अंक की छलांग लगाई जबकि निफ्टी में कुल 1,011.8 अंक की बढ़त रही। क्षेत्रवार सूचकांकों में औद्योगिक खंड में सर्वाधिक 1.80 प्रतिशत की तेजी रही जबकि रियल्टी खंड में 1.72 प्रतिशत, पूंजीगत उत्पाद खंड में 1.63 प्रतिशत और जन केंद्रित सेवाओं से जुड़े खंड में 1.44 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सोने में 1,400 रुपये की तेजी दर्ज 150 अरब आधार प्रमाणिकरण लेनदेन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में आधार प्रमाणिकरण लेन-देन की कुल संख्या 150 अरब पार कर गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि अब तक कुल 15011.82 करोड़ प्रमाणिकरण हो चुके हैं। दरअसल, आधार प्रमाणिकरण, आधार नंबर का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने की एक प्रक्रिया है।

व्ययान में कहा गया है कि यह आधार की व्यापक उपयोगिता और देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को प्रदर्शित करता है। आधार आधारित प्रमाणिकरण जीवन को आसान बनाने, प्रभावो कल्याण वितरण और सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं का स्वैच्छिक रूप से लाभ उठाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अकेले अप्रैल में लगभग 20 करोड़

आधार प्रमाणिकरण लेन-देन किए गए, जो 2024 में इसी महीने की तुलना में लगभग 8% अधिक है। व्ययान के अनुसार आधार ई-केवाईसी सेवा बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और व्यापार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अप्रैल 2025 के दौरान किए गए ई-केवाईसी लेनदेन (37.3 करोड़) की कुल संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की संख्या से 39.7% अधिक है। 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी लेनदेन की संख्या 2393 करोड़ को पार कर गई है।

अमेरिका से व्यापार करार को लेकर बैठकें आज से

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी वार्ता की प्रगति का आकलन करने, मुख्य वार्ताकारों को राजनीतिक मार्गदर्शन देने और आर्थिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए 17 मई से वाशिंगटन में मंत्रिस्तरीय बैठकें शुरू करेंगे।

व्यापार समझौते को लेकर गोयल की अमेरिका की दूसरी यात्रा

व्ययान के अनुसार आधार ई-केवाईसी सेवा बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और व्यापार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अप्रैल 2025 के दौरान किए गए ई-केवाईसी लेनदेन (37.3 करोड़) की कुल संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की संख्या से 39.7% अधिक है। 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी लेनदेन की संख्या 2393 करोड़ को पार कर गई है।

कार्यालय जिला नगरीय विकास अधिकरण (डूडा), गाजियाबाद
स्थित नगर निगम बिल्डिंग बेसमेंट नवयुक्त मार्केट गाजियाबाद-201001
ई-मेल आई0डी: dudagz.2015@rediffmail.com
दिनांक: 16.05.2025

सावजनिक सूचना

भारत सरकार द्वारा "एक पेड़ मां के नाम" अभियान का शुभारंभ किया गया है। उक्त अभियान पारंपरिक विधियों के साथ-साथ माताओं के प्रति सम्मान के भाग के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से निकायों में वृक्षारोपण की योजना बनाने एवं उनकी उत्तर-नीति सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया जाये जो अपेक्षा को पूरा है। उक्त अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु दिनांक 02 अगस्त 2025 तक चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

फेज-1 प्रदेश के नगरीय निकायों में दिनांक 21 से 23 मई 2025 तक तथा फेज-2 प्रदेश के नगरीय निकायों में दिनांक 05 जून से 31 अगस्त 2025 तक चिन्हित स्थलों पर निर्धारित लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण का अभियान चलाया जायेगा।

अन्यतः कराया जाना है कि अगस्त 2.0 योजना-नगरीय अग्रत एवं एनएलएम के संयुक्त तत्वाधान में अग्रत मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत "एक पेड़ मां के नाम" अभियान का क्रियान्वित किया जाना है। इस हेतु जनपद गाजियाबाद को निकायों में वृक्षारोपण हेतु जगहों का चिह्नान्तरण का लिया गया है।

उपरोक्त के परिचय में एन.यू.एलएम.योजना में जनपद गाजियाबाद को आच्छादित समस्त स्वयं सहायता समूहों को सदस्यों को सूचित किया जाता है कि चिन्हित स्थलों पर वृक्षारोपण/अनुसूच्य करने हेतु इच्छुक शहरी स्वयं सहायता समूह को सदस्य अपना प्रार्थना पत्र/आवेदन/समाप्तित सूचना/संबंधित स्थानीय निकाय कार्यालय में तैयार दिनांक में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके संबंध में अधिक जानकारी संबंधित निकाय कार्यालय/एन.यू.एलएम.योजना कार्यालय परल से ली जा सकती है।

परियोजना अधिकारी
डूडा गाजियाबाद

भारतीय गुणवत्ता परिषद

भारतीय गुणवत्ता परिषद (वर्चुअलीआई), भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है। वर्चुअलीआई का दायित्व गुणवत्तापूर्ण माल विकसित करना है और हमारी दिशानिर्देशना एवं सुनिश्चित करने की है कि हर नैतिक तक पहुँचने वाले उत्पाद और सेवाएं गुणवत्तापूर्ण हैं।

वर्चुअलीआई 'Engagement of an agency for Design, Supply, Installation, Integration, Commissioning and Maintenance of Interactive Digital Installations for experience centre at CCI Office' के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

अपेक्षाओं के विस्तृत विवरण के साथ Request for Proposal (RFP) tender reference no. CCI/PPD/0525/440, वर्चुअलीआई के वेबसाइट www.qcin.org पर लिखित संदेश (<https://qcin.org/work-with-us/#tenders>) के अंतर्गत देना जा सकता है।

इच्छुक पक्ष तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग तैयार करके, लिफाफों में 'उप निदेशक (एच ई डी), भारतीय गुणवत्ता परिषद, इंदिरा एवेन्यू, द्वितीय तल, 2, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002' को एक बाट्टी लिफाफों में लगे हुए एड्रेस में प्रस्ताव देना है। उल्लिखित डिनांक और समय के अनुरोध पर, निम्न 'Engagement of an agency for Design, Supply, Installation, Integration, Commissioning and Maintenance of Interactive Digital Installations for experience centre at CCI Office' लिखा होगा।

CCI'S BOARDS AND DIVISIONS
PADD, PPIP, NIAI, PIP, ONDC

Quality Council of India, Institution of Engineers Building, 11th Floor, 2, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, 110002, India.
qcin.org/india, qcin.org, qcin.org/india, qcin.org/india, qcin.org/india

फॉर्म नं. 63
[निमन 148(1) देखें]
नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय में (मूल कंपनी अधिक्षेत्र)
सी.पी. क्रमांक 400/2012 में
कंपनी अधिनियम, 1956 के मामलों में
और
मैसर्स सुपर प्रॉपर्टी मॉटेन्स प्रा. लि. (परिसमापन में) के मामलों में:
अपने दावे को साबित करने के लिए लेनदारों और कामगारों को नोटिस का विज्ञापन:

एतद्द्वारा सभी लेनदारों (प्रतिभूत और अप्रतिभूत) तरजीही लेनदारों के साथ-साथ कामगारों को नोटिस दिया जाता है, यदि उपरोक्त नामित कंपनी में से किसी से धीमा संबंधित है, तो उन्हें उपरोक्त नामित कंपनी के खिलाफ अपने संबंधित ऋण या दावों को साबित करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली के समक्ष दि. 20.06.2025 को या उससे पहले आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में इस तरह से जमा कर या आधिकारिक परिसमापक को डाक द्वारा भेजकर प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि निर्धारित तिथि से पहले उसके पास पहुंच जाए, जिसके साथ निर्धारित फॉर्म (फॉर्म नंबर -66) में ऋण या दावे को साबित करने वाला एक हलफनामा, जिसमें उनके संबंधित नाम, पते तथा ऋण या दावे के विवरण और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 ए और 530 के तहत प्राथमिकता का कोई स्वामित्व शामिल हो। कोई भी लेनदार (प्रतिभूत और अप्रतिभूत) तरजीही लेनदार और साथ ही कामगार यदि कोई हो, जो उपरोक्त कथित समय सीमा के भीतर प्रमाण का अपना हलफनामा जमा करने में विफल रहता है तो उसके ऋण के प्रमाणित होने से पूर्व, किसी भी लाभांश वितरण के लाभ से, या, जैसा भी मामला हो, ऐसे वितरण पर आपत्ति करने से उसे बंधित कर दिया जाएगा।

कोई भी लेनदार (प्रतिभूत और अप्रतिभूत) तरजीही लेनदारों और साथ ही कामगारों यदि कोई हो, जिसने अपना प्रमाण भेजा है, यदि आधिकारिक परिसमापक से लिखित में नोटिस द्वारा ऐसा आवश्यक हो, तो वह या तो स्वयं या अपने वकील द्वारा, ऐसे ऋण या दावे की जांच में ऐसे समय और स्थान पर उपस्थित होगा, जैसा कि ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा और अपने ऋण या दावे के उचित अतिरिक्त सबूत प्रस्तुत करेगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

दिनांक माह 2025
(एस. मीनाक्षी)
आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय से संबद्ध
8वीं मंजिल, लोक न्याय कक्ष, खास मार्केट
नई दिल्ली-110003, फोन: 011-24693393-94
कंपनी (न्यायालय) नियम 1959 के प्रारंभ संख्या 66 को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट www.mca.gov.in, www.delhiol.com पर जाएं।
सीबीडी 07104/11/0015/2526